International Journal of Applied Research 2019; 5(3): 65-68

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2019; 5(3): 65-68
www.allresearchjournal.com
Received: 19-01-2019
Accepted: 24-02-2019

Dr. Ranu Sharma
Supervisor & Associate Professor, H.O.D K.A. (PG) College Kasganj, Dr. B.R.A.U. Agra Uttar Pradesh, India

Manoj Kumar
Research Scholar, K.A.(PG) College, Kasganj, Uttar Pradesh, India

Corresponding Author:
Dr. Ranu Sharma
Supervisor & Associate Professor, H.O.D K.A. (PG) College Kasganj, Dr. B.R.A.U. Agra Uttar Pradesh, India

भारत में कौशल विकास में उभरती हुयीं संभावनायें

Dr. Ranu Sharma and Manoj Kumar

सारांश
देश के आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए कौशल, ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी योग्यता वो प्रेरक बल हैं जो देश को आगे ले जाने में मदद करते हैं। वर्तमान वैश्विक माहौल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती से निपटने में वे देश आगे हैं जिन्होनें कौशल एवं तकनीकी के उच्च स्तर को छू लिया है। श्रम ब्यूरो की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औपचारिक रूप से कुशल कार्यबल का वर्तमान आकार केवल 2 प्रतिशत है। पिछले कई दशकों में शिक्षा के गिरते स्तर और पिछड़ेपन के कारण पारम्परिक शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के एक बड़े वर्ग को रोजगार सम्बन्धी योग्यता की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता, आचार, विचार की कमी है। इतिहास इस बात का गवाह है कि प्राचीन काल में भारत अपने कौशल, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, खगोल, गणित आदि के लिए विश्व में जाना जाता था और आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था शानदार मस्तिष्कों को जन्म दे रही है लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाली प्रतिभाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी देखी गई है और दूसरे हमारी शिक्षा पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नही हुआ है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति का आधार प्रौद्योगिकी और तकनीकी नहीं है जिसके कारण उच्चशिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है। इसके लिए हमें अपनी शिक्षा पद्धति में सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगें। युवाओं को आवश्यक व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करनी होगी जिससे वह शिक्षा का समुचित प्रयोग कर सकें। विद्यालयों में तकनीकी एवं कार्य पर आधारित शिक्षा का प्रयोग युवा उद्योगों और फैक्ट्रियों में कर सकेंगें और आसानी से रोजगार पा सकेंगें। इसके साथ ही साथ व्यवहारिक रोजगारपरक शिक्षा एवं कौशल आधारित शिक्षा पद्धति अपनाकर हम बेरोजगारी पर काबू पा सकते हैं।

कूटशब्दः कौशल विकास, आर्थिक, सामाजिक विकास

प्रस्तावना
कुशल भारत और सफल भारत की नींव कौशल विकास के बिना अधूरी है यदि देश को वर्तमान और भविष्य में प्रगति के रास्ते पर चलने के लिए कौशल विकास का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। जब देश की बागडोर हुनरमंद हाथों में होगी तो देश नित नई ऊँचाईयों को छुएगा और युवाओं को नई दिशा मिलेगी। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2015 को "स्किल इंडिया कार्यक्रम" का सूत्रपात किया जिसके तहत 2022 तक देश के 40 करोड़ लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में हुनरमंद बनाने का लक्ष्य है। जिसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को कुशल बना कर उन्हें सशक्त बनाना है जिससे युवाओं को और अधिक रोजगार मिल सके तथा वो अपने कार्य क्षेत्र में और अधिक निपुण बन सकें।

विश्व में जनसंख्या के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं और युवा आबादी के मामले में हम दुनिया में सबसे ऊपर हैं। हमारे देश में 54 फीसदी 25 वर्ष और 65 फीसदी 35 वर्ष की आयु से कम की है। यानि कि वर्तमान में 65 फीसदी युवा कामगार आयु समूह का है। यही युवा देश की दशा दिशा सुधारकर उसे तरक्की के रास्ते पर ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है जब हम इस कामगार युवा शक्ति का प्रयोग देश की आर्थिक तरक्की उन्नति में कर सकते हैं लेकिन यह तभी संभव है जब देश के युवा शिक्षित, प्रशिक्षित और दक्षता से लबालब होंगें। दुनिया में तेजी से तकनीकी में बदलाव हो रहा है ऐसे में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती तकनीक के साथ खुद को बदलना होगा। तकनीकी से तालमेल बैठाने में युवा अगर पीछे रहे तो भविष्य में 2030 तक लगभग 2 अरब युवा आबादी बेरोजगार हो जाएगी। डेलाइट की रिपोर्ट के मुताबिक चौथी औद्योगिक क्रान्ति में रोजगार के खूब मौके होंगें लेकिन युवाओं के सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं होंगी। तकनीकी परिवर्तन से न सिर्फ श्रमिकों की भूमिका बदलेगी बल्कि उपभोक्ताओं और प्रतिद्वंद्वियों की भूमिका में भी तेजी से बदलाव आएगा उद्योग जगत को इस दिशा में अभी से काम करने की जरूरत है।

"द ग्लोबल बिजनेस कोलिशन फॉर एजुकेशन" के अनुसार युवाओं को रचनात्मक सोच के तहत तकनीकी समझ विकसित करनी होगी उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही बेहतर प्रशिक्षण भी देना होगा। यह भी माना जा रहा है कि 2030 तक विकसित देशों में पॉच करोड़ नौकरियों के लिए युवा शक्ति की कमी होगी और भारत में पांच करोड़ युवा नौकरियाँ ढूंढ रहें होंगें और उन्हें ये नौकरियाँ तभी मिल पायेंगी जब भारतीय युवक श्रमिक विदेशी भाषा, संस्कृति एवं जलवायु में काम करने में सक्षम हो और तकनीकी रूप से अधिक कुशल होंगें। वर्ष 2025 तक विश्व की कामकाजी आबादी (18 प्रतिशत) के 5 में से 1 भारतीय होंगें। हाल की कौशल अंतराल रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि 2022 तक केवल भारत में ही सभी प्रमुख 24 क्षेत्रों में 109 से अधिक विलियन वृद्विशील मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी। वहीं भारत के 93 प्रतिशत मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अनौपचारिक माध्यमों से कुशलता प्राप्त करते हैं जिसके कारण उनके पास औपचारिक शिक्षा और प्रमाणपत्रों का अभाव होता है। यही कारण है कि वे कौशल प्रतिद्धन्दता में पीछे रह जाते हैं।

दुनिया में बढ़ती बेरोजगारी एक बहुत बड़ा संकट है इससे कोई भी देश अछूता नहीं है। विकसित कहे जाने वाले अमेरिका में भी बेरोजगारी दर चार फीसदी है वहीं चीन में भी बेरोजगारी पर अंकुश नही लग पाया है। हमारे देश की हालात तो और भी खराब है जिसमें लगभग 4.5 करोड़ पढे लिखे पंजीकृत बेरोजगार हैं जिनमें 20 फीसदी युवा हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 30 फीसदी युवा जिनकी उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच है, किसी भी रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण के दायरे में नहीं हैं। सेन्टर ऑफ मॉनीटरिंग इंडियन इकोनोमी (सीएमआईई) ने अपनी हाल की एक रिपोर्ट में कहा था कि देश में बीते साल 1.10 करोड नौकरियाँ कम हुई हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) के एक सर्वेक्षण के हवाले से यह खुलासा हुआ कि वर्ष 2017–18 के दौरान भारत में बेरोजगारी दर बीते 45 वर्षों में सबसे ज्यादा रही। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में वर्ष 1972–73 के बाद बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई है। शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 7.8 फीसदी है वहीं ग्रामीण इलाकों में यह दर 5.3 फीसदी है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में शिक्षित युवतियों में वर्ष 2004–05 से 2011–12 के बीच बेरोजगारी की दर 9.7 से 15.2 फीसदी के बीच थी जो वर्ष 2017–18 में बढ़ कर 17.3 फीसदी तक पहुंच गई। ग्रामीण इलाकों में शिक्षित युवकों में इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी दर 3.5 से 4.4 फीसदी के बीच थी वर्ष 2017–18 में बढ़ कर 10.5 फीसदी तक पहुंच गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में 15 से 29 साल की उम्र वाले युवकों में बेरोजगारी की दर वर्ष 2011–12 में जहॉ पांच फीसदी थी वहीं वर्ष 2017–18 में यह तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ कर 17.4 फीसदी तक पहुंच गई और इसी उम्र की युवतियों में यह दर 4.8 से बढ़ कर 13.6 फीसदी तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि खेती अब पहले की तरह मुनाफे का सौदा नहीं रही। इसी कारण ग्रामीण इलाके के युवा रोजगार की तलाश में अब खेती छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आने लगे हैं और शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाले निर्माण क्षेत्र में आई मंदी के चलते नौकरियां कम हुई हैं। रोजगार के अभाव में शिक्षित बेरोजगारों में हताशा लगातार बढ़ रही है नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के आंकड़े इस बात के गवाह हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल मार्च में रेलवे में 90 हजार नौकरियों के लिए ढाई करोड़ बेरोजगारों ने आवेदन किया था। इसी तरह गुजरात में 12 हजार नौकरियों के लिए 9.70 करोड़ ने आवेदन भेजा था। यही हाल लगभग पूरे देश भर का है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0एल0ओ0) का आंकलन है कि भारत में बेरोजगारों की तादाद वर्ष 2019 में बढ़कर लगभग दो करोड़ तक पहुंच जाएगी वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जमीनी हालत इससे भी भयावह है और बेरोजगारी अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो हालात विस्फोटक होने का अंदेशा है।

भारत वर्तमान में कुशल श्रमिक बल के लिए एक केन्द्र बनने को तैयार है इसलिये कौशल विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। भविष्य में अनुमानित कुशल श्रम बल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2022 तक 500 मिलियन सुदृढ़ कुशल एवं प्रशिक्षित जन बल तैयार करने का लक्ष्य रखा है। आंकड़ों की माने तो अब तक देश में कुल श्रमबल में से केवल 4.69 प्रतिशत लोगों को ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। जो कि कुछ विकासशील देश हमसे इस मामले में आगे हैं और जहॉ तक विकसित देशों की बात है तो अमेरिका में कुशल श्रम बल का 52 प्रतिशत है ब्रिटेन में 68 जापान में 80 चीन में 46 जर्मनी में 70 और दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत तक है। इन देशों में पिछले 50–60 वर्षों में सरकार व उद्योगों के प्रयास से ही वहां की श्रम शक्ति हुनरमंद बनी है।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीसी) की स्थापना राष्ट्रीय कौशल नीति के तहत यूपीए–2 के कार्यकाल में वर्ष 2009 में की गई थी लेकिन वर्षों में इस मिशन पर बहुत काम नही हुए। इसके पश्चात एनडीए सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में चल रही बहुत सारी कौशल विकास योजनाओं को कौशल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत लाकर इसे मजबूती देने का प्रयत्न किया है। जिसका उद्देश्य तेजी, गुणवत्ता और निरंतरता के साथ कौशल हासिल करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल ऋण योजना और कौशल विकास व उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा करके सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि आने वाले दशक में भारत में कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। इससे न केवल युवाओं का व्यक्तिगत विकास होगा बल्कि देश की आर्थिक उन्नति भी होगी। इस योजना के प्रमुख अंग हैं आई0आई0टी0, आई0आई0एम0, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व अन्य 40 हजार उच्च शिक्षण संस्थानों में एक से छः माह के तकनीशियन एवं वोकेशनल कोर्स चलाया जाना इसके साथ ही कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए पांच हजार रूपये से लेकर डेढ़ लाख रूपये तक के कर्ज भी दिये जायेंगें। एक अनुमान के मुताबिक 2022 तक अर्थव्यवस्था के 24 सेक्टरों में 11 करोड़ अतिरिक्त जनशक्ति की जरूरत होगी। रिटेल, रीयल एस्टेट, परिवहन, स्वास्थ्य और ब्यूटी पार्लर से जुड़े क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होंगें। इस योजना में यह भी अनुमान लगाया गया है कि कृषि क्षेत्र से 2.5 करोड़ लोग गैर–कृषि रोजगार पाने के लिए गॉवों को छोड़ने के लिए विवश होंगें। अगर समय रहते इन युवाओं को हुनरमंद और रोजगार योग्य नहीं बनाया गया तो समाज में अस्थिरता की स्थिति पैदा होगी। इसी को ध्यान में रखकर कौशल भारत देश के 40 क्षेत्रों में पाठ्यक्रम पेश करता है जो उद्योगों और सरकार के नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मानकों के अनुरूप होते हैं। यह कोर्स एक व्यक्ति को कार्य के व्यवहारिक विस्तार और उसके तकनीकी अभ्यास में ध्यान केन्द्रित करने में मदद करता है जिससे वह अपनी नौकरी के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सके और कम्पनी को उसके प्रोफाइल के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ना पड़े। देश में पहली बार आजादी के 68 साल बाद कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया जिसमें भारतीय कार्यक्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक नवांगतु को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य को हासिल किया गया है। भारत के कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार और बेहतर नीतियों को देखा गया है जिससे देश के कर्मचारी फिर से सक्रिय हुए हैं।

देश में 70 से अधिक कौशल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं जिनमें से प्रत्येक के योग्यता मानदंड सम्बन्धी नियम, प्रशिक्षण का खर्च, बजट अवधि प्रशिक्षण के परिणाम एवं देखरेख निगरानी और

प्रशिक्षण प्रक्रिया के द्वारा नीति की समीक्षा करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। जिसके लिए निवेश, वित्तपोषण, आंकलन मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रदाता का पैनल तैयार करने से लेकर कौशल विकास प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के पूरे दायरे को तर्कसंगत बनाने में सहायता होगी और साझा लक्ष्य प्राप्त करना आसान रहेगा। योजना का मौलिक उद्देश्य कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ गये छात्रों को उद्योग सम्बन्धी कौशल आधारित प्रशिक्षण पूर्णतः निशुल्क प्रदान करना है। जिसका 12000 रूपये प्रति लाभार्थी खर्च भी शासन वहन करता है। कौशल प्रशिक्षण (जिसकी अवधि 3 माह से 1 वर्ष अधिकतम होती है) पूरा होने पर युवा प्रशिक्षणार्थी को "नेशनल स्किल डवलपमेन्ट कारपोरेशन (एनएसडीसी)" जो एक गैर लाभ कम्पनी है, द्वारा नियुक्त "मूल्यांकन एजेन्सी सेक्टर स्किल काउन्सिल (एस0एस0सी0)" की जांच प्रक्रिया द्वारा सफल मूल्यांकित किये जाने पर शासन की ओर से एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो उन्हें रोजगार पाने में मदद देगा जिससे उनका भविष्य संवरेगा। इस योजना में प्रति उम्मीदवार को शासन द्वारा औसतन 8000 रूपये तक के भौतिक पुरस्कार भी दिये जाते हैं। इस योजना की वेबसाईट www.pmkvyofficial.org है जिस पर योजना की सम्पूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध है इसके लिए एक टोल फ्री नम्बर 1800–1028–056 पर कॉल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने नीति आयोग में स्किल डवलपमेन्ट मिशन के तहत कौशल विकास योजना लाकर देश के युवाओं में नई जागरूकता का संचार किया है। उन्होने अपने भाषण के दौरान कहा था कि "हमारा देश भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं वाला देश है और कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ भारत के लोग नहीं रहते हों और हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाता है। हमें इसकी ताकत को पहचानना होगा।" कौशल विकास की पूरी लहर वर्तमान में बेहद सकारात्मक दिख रही है जो दुनिया में उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की शक्ति को बढ़ा सकती है। वर्तमान में लगभग 2,300 केन्द्रों के एन0एस0डी0सी0 के 187 प्रशिक्षण साझेदार हैं यह योजना निम्न लक्ष्यों पर केन्द्रित है–

1. देश में मौजूद कार्यबल की उत्पादकता को बढ़ाना और देश की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण तथा प्रमाणन का समन्वय करना।
2. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार योग्य बनाने और अपनी जीविका सुनिश्चित करके अपने जीवन को प्रगति के रास्ते पर ले जाना।
3. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित कर उनकी रोजगार क्षमता तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु कौशल–प्रमाणन को मौद्रिक पुरस्कार।
4. प्रमाण प्रक्रिया में मानवीकरण को प्रोत्साहन तथा कौशल पंजीकरण व्यवस्था का सृजन।

कौशल विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करते समय भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। आज जिस हुनर और कौशल के प्रति हम आशान्वित हैं जरूरी नहीं कि उनकी आवश्यकता और जरूरत हमेशा बनी रहे। रोबोटिक्स, इन्टरनेट, आर्टीफिशियल इंटेलीजेन्स, बायोटेक्नोलॉजी, डाटा–एन–लिटिक्स, ई–कॉमर्स आदि क्षेत्रों में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, वे करोड़ों मौजूदा नौकरियों को निगल जाएगें। ऐसी स्थिति में देश में बेरोजगारी और बढ़ेंगी यह भी तथ्य सामने आये हैं कि भारतीय युवाओं को कौशल विकास के नाम पर उच्च शिक्षा से वंचित करना भी उनके साथ अन्याय है क्योंकि सीखी हुई खास स्किल्स से युवा रातों रात कुशलता नही प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा औद्योगिक जगत की कार्य दशा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। देश में निर्माण उद्योगों, खेती–खनन और भवन–निर्माण जैसे क्षेत्रों में नियोक्ता और श्रमिकों के सम्बन्ध बहुत सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण नही हैं। ऐसा देखा गया है कि जो बर्ताव उद्योगों में कॉन्ट्रेक्ट लेबर के साथ किया जाता है वैसा व्यवहार प्रशिक्षित भारतीय युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में एन0एस0डी0सी0 के चेयरमैन एस रामदोराई का यह कथन सही है कि आने वाले दशक में विश्व बाजार में भारत को सस्ती जनशक्ति की सप्लाई पर ध्यान न देकर प्रशिक्षित व हाईटेक जनशक्ति पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय उद्योगों में स्थायी और ठेके पर नियुक्त श्रमिकों की दोहरी व्यवस्था समाप्त करनी होगी। 'मेक इन इंडिया' और 'कौशल विकास' की राष्ट्रीय योजनाओं की कामयाबी तभी संभव है जब हम हुनरमंद भारतीय युवाओं के लिये आत्मनिर्भर जीवन की शुरूआत कर पाने में सक्षम हो पायेंगें।

मौजूदा सरकारी आकडों के विश्लेषण से पता चलता है कि 96 प्रतिशत एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विकास कार्यों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह तथ्य सामने आये हैं कि इन जिलों में 2018 फरवरी 2019 के बीच आर्थिक एवं कौशल विकास के क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान यह पाया गया कि 112 में से 108 जिलों में आर्थिक विकास एवं कौशल निर्माण के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के परिणाम निराशाजनक हैं। सेन्टर फॉर सांइस एण्ड इन्वायरमेन्ट (सी0एस0ई0) और डाउन टू अर्थ द्वारा 5 जून 2019 को आने वाली 'स्टेट ऑफ इण्डिया एनवायरनमेन्ट 2019' रिपोर्ट के अनुसार इन योजनाओं का लक्ष्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें सक्षम बनाना था जिससे कमजोर तबके के युवाओं का भी विकास संभव हो सके। डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल प्रोग्राम के तहत देश के 112 अल्पविकसित जिलों का पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास करना था जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आर्थिक एवं कौशल विकास और बुनियादी ढॉचे का मजबूत करना प्रमुख है जिसका सीधा सीधा असर–नागरिकों के जीवन और आर्थिक समृद्धता पर पड़ेगा। 2018 के दौरान बेरोजगारों की संख्या में लगभग 1.1 करोड की वृद्धि हुई है जो पिछले 27 महीनों में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। इस उच्च बेरोजगारी दर के लिए युवाओं में उपलब्ध नौकरियों के अनुरूप आवश्यक कौशल को कमी की जिम्मेदार माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दम पर ही सरकार ने रोजगार पैदा करने का वादा किया था जिसके लिए 2020 तक 12,000 करोड़ का बजट पास किया गया था जिसमें अगले चार सालों के लिए योजना (2016–2020) को मंजूरी दी जिसके तहत योजना के विस्तार को तीन प्रमुख आधारों पर केन्द्रित किया गया।

- प्रशिक्षण के बुनियादी ढॉचे के मानकीकरण और प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्पष्ट गुणवत्ता मानक।
- अन्तिम परिणाम के एक उपाय के रूप में नियुक्तियों पर अनवरत फोकस।
- उद्देश्य मूलक और प्रक्रिया आधारित निर्णय लेने के ढॉचे के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि प्रमुख तीन प्रमुख स्तम्भों के आधार पर पी0एम0के0वी0वाई0 के लिए सुधरे हुए मानकों को लागू करना मुख्य चुनौती है। अब तक 27 राज्यों में 527 प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र आवंटित किए गए थे जिसमें 328 केन्द्रों को अब तक स्थापित किया गया है। इतने बड़े लक्ष्यों को संख्यात्मक दृष्टि से प्राप्त करने के दौरान सीखे गये कौशलों की गुणवत्ता प्रभावित नही होनी चाहिए। इसके लिए कुशल प्रशिक्षकों की एक फौज तैयार करनी होगी। राष्ट्रीय कौशल निगम के अनुसार 2022 तक देश में लगभग 7 लाख प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। कौशल प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार ही एकमात्र चुनौती नही है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर स्पर्धा करने योग्य बनने के लिये कौशल की गुणवत्ता में सुधार होना भी अपने आप में एक चुनौती

है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है ऐसे में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि उसकी कामगार जनता बहुत कुशल सक्षम और जागरूक हो क्योंकि 2020 तक भारत में जनसंख्या की औसत आयु 28 वर्ष हो जाएगी जो आने वाले वक्त में भारत की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग युवा होगा। यह देश के लिए स्वर्णिम अवसर के साथ चुनौती भी है। हर साल 13 मिलियन से ज्यादा भारतीय काम करने वाली उम्र में प्रवेश करते हैं। आई0टी0आई0 संस्थानों, पॉलीटैक्निकों, स्नातक कॉलेजों, प्रोफेशनल कॉलेजों आदि में प्रशिक्षण और शैक्षणिक क्षमताओं को जोड़कर देखें तो देश में कुल 3 मिलियन वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता है। इन संस्थानों में किसी शिक्षित / कुशल भारतीय के निर्माण पर 1 से 4 साल तक लगते हैं जिसके कारण प्रशिक्षण के लिए लंबी अवधि की तुलना में धीमी गति से कौशल विकास की गति को बनाए रखना बहुत आवश्यक है।

स्किल इंडिया के तहत देश की महिला उद्यमियों को भी पी0एम0के0वी0वाई0 द्वारा शिक्षित प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे उनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण संभव हो सके। इसके उद्देश्य महिलाओं की उन्नीति एवं विकास के माध्यम से देश में सकारात्मक माहौल बनाना है जिससे महिलाऐं अपनी क्षमता कुशलता को पहचान सकें और शिक्षा, रोजगार, समान पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सके क्योंकि महिलाऐं जब समर्थ सम्पन्न और सक्षम होगी तो देश अपने आप तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के 2010–11 के आंकड़ों के अनुसार 2010–11 में महिला उद्यमी 22.3 फीसदी थीं। कौशल विकास की पूरी लहर इस समय बेहद सकारात्मक दिख रही है। जो दुनिया में उभरतें बाजार वाली अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की शक्ति को बढ़ा सकती है और निवेश के ठिकाने के रूप में इसके आकर्षण को बढ़ाने में योगदान भी कर सकती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल प्रमाणन के लिए मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने में तथा उसके कारण उनकी रोजगार प्राप्त करने की क्षमता तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी योजना का लक्ष्य लोगों को पहले मिली शिक्षा को समझकर उनके वर्तमान कौशन को पहचानना भी है।

यह तो मानना पड़ेगा कि सम्पूर्ण विश्व आज भारत की ओर टक–टकी लगाए देख रहा है जिसके पास युवा ऊर्जा का भण्डार है जो आने वाले समय में भारत की तस्वीर और भाग्य बदलने की क्षमता रखता है बस जरूरत है तो उसे सही दिशा, मार्गदर्शन, शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण और प्रयास की जिससे सुखी, समृद्ध और सम्पन्न भारत का निर्माण हो सके। यह तभी संभव है जब देश के युवा कौशल सम्पन्नता एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान से लैस होंगें।

संदर्भ सूची

1. नाटाणी प्रकाश नारायणः ग्रामीण गरीबी तथा बेरोजगारी : कारण और समाधान, कुरूक्षेत्र पत्रिका, जुलाई 2007, पृष्ठ 40–44
2. चिनाय दिलीपः भारत में कौशल विकास परिदृश्य की नयी परिभाषा, योजना पत्रिका, अक्टूबर 2015, पृष्ट 9–12
3. मायरा अरूण व पडकी मदनः रोजगार,उद्यम, प्रौद्योगिकी एवं कौशल, योजना पत्रिका, अक्टूबर 2015, पृष्ठ 13–18
4. कुमारी पवन रेखाः स्किल इंडिया फ्रेमवर्क : आधी आबादी के लिए पूरा मौका, योजना पत्रिका, अक्टूबर 2015, पृष्ठ 35–37
5. सिंह अरविन्द कुमारः कृषि क्षेत्र में कौशल विकास की आवश्यकता, योजना पत्रिका, अक्टूबर 2015, पृष्ठ 51–54
6. सिंह डॉ0 धर्मेन्द्रः प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, शिवांक प्रकाशन दरियागंज दिल्ली –2 वर्ष 2017
7. बरारा सरिताः तेजी से होता कौशल विकास, उद्योग व्यापार पत्रिका, मार्च 2018
8. कुमार आलोकः रोजगार के समाधान के लिए कौशल विकास पर है जोर, उद्योग व्यापार पत्रिका, मार्च 2018
9. विश्वबैंक की रिपोर्टः 2010–11
10. श्रम व्यूरो की रिपोर्ट 2014
11. द ग्लोबल विजनेस कोलिशन फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट
12. कौशल अंतराल रिपोर्ट
13. सेन्टर ऑफ मॉनीटरिंग इंडियन इकोनोमी (CMIE) की रिपोर्ट
14. बेरोजगारी दर के ऑकड़े
15. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I.L.O) का आंकलन
16. सेंटर फॉर साइंस एवं इन्वायरमेंट (CSE) और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट जून 2019